

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3626

जिसका उत्तर मंगलवार 08 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

**कागज मिलों का पुनरुद्धार**

**3626. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

डॉ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एक लाख मीट्रिक टन अधिष्ठापित क्षमता वाली कागज मिलों में वर्ष 2015 से उत्पादन को निलंबित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके मुख्य कारण क्या हैं;
- (ख) क्या उक्त कागज मिलों के कर्मचारियों को लम्बे समय से वेतन नहीं दिया गया है जिस कारण उक्त कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने कर्मचारियों ने आत्महत्या की है;
- (घ) किन-किन कागज मिलों ने सरकार से पुनरुद्धार पैकेज की मांग की है;
- (ङ) क्या मंत्रालय ने नीति आयोग के समक्ष 1347 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज का निवेदन किया है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर नीति आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (छ) सरकार द्वारा इन रुग्ण कागज मिलों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**

**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क): कार्यशील पूंजी की कमी की वजह से हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन (एचपीसी) की इकाइयों अर्थात् कछाड़ पेपर मिल (सीपीएम) और नगांव पेपर मिल (एनपीएम) में उत्पादन क्रमशः अक्टूबर, 2015 और मार्च, 2017 से रुका हुआ है।

(ख): एनपीएम के कर्मचारियों को पिछले 8 माह का वेतन और सीपीएम के कर्मचारियों को पिछले 10 माह का वेतन अदा नहीं किया गया है। तथापि, वेतन का भुगतान न होने की वजह से कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या करने के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): एचपीसी ने अपनी मिलों - नगांव पेपर मिल और कछाड़ पेपर मिल के लिए पुनरुद्धार पैकेज की मांग की है।

(ङ से छ): हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन (एचपीसी) के पुनरुद्धार के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह भारी उद्योग विभाग के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव में सीपीएम और एनपीएम के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु बजटीय सहायता भी शामिल है।

\*\*\*\*\*